



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

हि  
6/3/89

सं० 130]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 1989/फाल्गुन 25, 1910

No. 130]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 1989/PHALGUNA 25, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

विधि और व्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1989

का. प्रा. 194(अ) -- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित  
प्रादेश मंत्रालय की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

प्रादेश

राष्ट्रपति ने, बिहार राज्य की विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री फैयाजुल  
आजम को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उप-  
धारा (3) के निर्वाचनों के अनुसार, निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय के  
आधार पर, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (i) के अधीन  
तारीख 17 जुलाई, 1984 से 4 वर्ष की अवधि के लिए तारीख 28  
नवंबर, 1985 के अपने आदेश द्वारा निर्वाचित कर दिया था।

श्री फैयाजुल आजम ने अपने मामले के पुनर्विचार और राष्ट्र-  
पति के पूर्वोक्त आदेश के अधीनस्वयं द्वारा उपगत निरुद्धता के अपवर्धित  
भाग को रद्द करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन यथा  
साक्ष्यित अर्जी तारीख 18 फरवरी, 1988 को राष्ट्रपति के समक्ष दाखल  
की थी।

और निर्वाचन आयोग की राय (उपायध वेबें) है कि श्री फैयाजुल  
आजम की उक्त अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी  
उपबंध के अधीन समर्थित नहीं है परिणामतः यह धारणीकार किए जाने  
योग्य है,

यतः भारत के राष्ट्रपति की हैसियत में, भारत वेक्टरामत उक्त  
अर्जी अस्वीकार करता है।

भार. वेक्टरामत,  
भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1989

### भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1988 के संदर्भ मामला सं. 1 (लो. प्र. अधि.)

[लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश]

संदर्भ : बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री फैयाजुल आज़म, की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन अपनी निरुद्घता के रह किए जाने/पुनर्विलोचन के लिए राष्ट्रपति को अर्जी।

राय

1.1 राष्ट्रपति ने, बिहार राज्य की विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री फैयाजुल आज़म को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (3) के निबंधनों के अनुसार, निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई राय के आधार पर, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन, तारीख 17 जुलाई, 1984 से, अर्थात् 1979 की सिविल अपील सं. 3911 में उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख से, 4 वर्ष की अवधि के लिए, तारीख 28 जनवरी, 1985 के अपने आदेश द्वारा, निरहित कर दिया था।

1.2 श्री फैयाजुल आज़म ने, अपने मामले में पुनर्विलोचन और राष्ट्रपति के पूर्वोक्त आदेश के अधीन स्वयं द्वारा उपगत निरुद्घता के अपर्यवर्तित भाग के रह किए जाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन यथा तात्पर्यित वर्तमान अर्जी, तारीख 18 फरवरी, 1988 को राष्ट्रपति के समक्ष फाइल की है। राष्ट्रपति ने, आयोग को राय जानने के लिए उक्त अर्जी आयोग को निर्देशित की है।

2.1 मेरी राय में, वर्तमान अर्जी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी भी उपबंध के अधीन कायम रखे जाने योग्य नहीं है। निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा तारीख 6 अगस्त, 1975 से यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति को यह विनिश्चित करना है कि निर्वाचन अर्जी में उच्च न्यायालय या निर्वाचन अपील में उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के लिए, दोषी ठहराए गए व्यक्ति को निरहित किया जाना चाहिए या नहीं और यदि किया जाना चाहिए तो कितनी कालावधि के लिए। ऐसा विनिश्चित करते समय राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क (3) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेंगे और आयोग द्वारा दी गई राय के अनुसार कार्य करेंगे। उक्त धारा 8क (1) के अधीन राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसा कोई उपबंध नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रपति के विनिश्चय के विरुद्ध, राष्ट्रपति सहित किसी प्राधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती हो या उसका पुनर्विलोचन कराया जा सकता हो। उक्त धारा 8क, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अध्याय 3 में समाविष्ट है और इस संबंध में यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि इस अध्याय के अधीन निरुद्घता की किसी अवधि को रह या कम करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन आयोग की अध्यारोही शक्तियाँ, उक्त धारा 8क के अधीन जाने वाली निरुद्घताओं से भिन्न निरुद्घता के अभिव्यक्त अपवाद के कारण, सीमित हैं। यद्यपि उक्त अधिनियम की धारा 8क (2) के अधीन, धारा 8क, जैसी कि यह ऊपर निविष्ट निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ के ठीक पूर्व थी, के अधीन उपगत निरुद्घता की अवधि को राष्ट्रपति द्वारा रह या कम कर दिए जाने के लिए उपबंध किया गया था, तथापि ऊपर निविष्ट संशोधन अधिनियम, 1975 के प्रारंभ के पश्चात्, धारा 8क (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निरहित व्यक्ति के मामले में कोई उपबंध नहीं किया गया है। अतः धारा 8क (2) के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन निरुद्घता के मामले में लागू नहीं होते।

2.2 उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए, संदर्भ मामला सं. 1 में, जो एक अर्जी में, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बलवान सिंह द्वारा राष्ट्रपति को की गई थी, राष्ट्रपति को तारीख 6 अप्रैल, 1981 को दी गई राय में यह अभिनिर्धारित किया था कि, श्री बलवान सिंह की अर्जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी उपबंध के अधीन कायम रखी जाने योग्य नहीं है। आयोग की उक्त राय के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री बलवान सिंह की उक्त अर्जी 8 जून, 1988 को अस्वीकार कर दी थी। उक्त धारा 8क (1) के अधीन निरुद्घता के संबंधित विधि में, आयोग द्वारा दी गई उक्त राय के पश्चात्, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मेरी यह राय है और तदनुसार यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि श्री फैयाजुल आज़म की उक्त अर्जी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के किसी भी उपबंध के अधीन कायम रखी जाने योग्य नहीं है। अतः वह अस्वीकार किए जाने योग्य है। राष्ट्रपति से प्राप्त यह निर्देश, उपरोक्त आदेश की मेरी राय के साथ उनकी वापस किया जाता है।

आर. वी. एस. पेरियास्वामी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली,

[फा. सं. 7 (24)/84-वि -II]

ख. 28 दिनांक, 1988 एम. के. रामस्वामी, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1989

S.O. 194(E) :—The following Order made by the President is published for general information :—

### ORDER

Whereas Shri Faiyazul Azam, a former Member of the Legislative Assembly of the State of Bihar was disqualified by the President by his Order dated the 28th January, 1985, under sub-section (1) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951, for a period of 4 years from the 17th July, 1984, on the opinion tendered by the Election Commission in terms of sub-section (3) of Section 8A of the said Act;

And whereas Shri Faiyazul Azam a petition dated the 18th February, 1988, before the President purporting to be under Section 8A of the said Act for review of his case and removal of the unexpired portion of disqualification incurred by him under the aforesaid Order of the President;

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexure) that the said petition of Shri Faiyazul Azam is not maintainable under any provision of the Representation of the People Act, 1951, and that it is, therefore, liable to be rejected:

Now, therefore, I, R. Venkataraman, President of India, do hereby reject the said petition.

R. VENKATARAMAN,  
President of India

New Delhi, 6th March, 1989.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Before the Election Commission of India

Reference Case No. I (RPA) of 1988

[Reference from the President under section 8A (3) of the Representation of the People Act, 1951]

In re : Petition of Shri Faiyazul Azam, a former member of Bihar Legislative Assembly to the President for removal/review of his disqualification under section 8A of the Representation of the People Act, 1951.

**OPINION**

1.1 Shri Faiyazul Azam, a former member of Bihar Legislative Assembly, was disqualified by the President by his order dated 28th January, 1985, under Section 8A (1) of the Representation of the People Act, 1951 for a period of 4 years from 17th July, 1984, i.e., from the date of the Supreme Court's order in Civil Appeal No. 3011 of 1979, on the opinion rendered by the Commission in terms of Section 8A(3) of the said Act.

1.2 The present petition dated 18-2-1988 has been filed by Shri Faiyazul Azam before the President purporting to be under section 8A of the said Act for review of his case and removal of the unexpired portion of the period of disqualification incurred by him under the aforesaid order of the President. The said petition has been referred by the President to the Commission for its opinion.

2.1 In my opinion, the present petition is not maintainable under any provisions of the Representation of the People Act, 1951. Under Section 8A of the said Act as amended by the Election Laws (Amendment) Act, 1975, w. e. f. 6th August, 1975, the President is to decide under sub-section (1) of that section whether a person found guilty of corrupt practice at an election by a High Court in an election petition or by the Supreme Court in an election appeal should be disqualified and, if so, for what period. While so deciding, he shall obtain the opinion of the Election Commission under Section 8A (3) of the said Act and shall act according to the opinion tendered by the Commission. The decision of the President given under the said section 8A (1) is final and there is no provision in the said Act whereunder the above decision of the President can be appealed against or reviewed by any authority in-

cluding the President. The said section 8A is included in Chapter III of the Representation of the People Act, 1951 and it may be relevant to mention in this connection that the overriding powers of the Commission under section 11 of the said Act to remove or reduce the period of any disqualification under the Chapter, are limited by reason of an express exception to disqualifications other than those under the said section 8A. Though under section 8A (2) of the said Act, a provision had been made for removal or reduction by the President of the period of disqualification incurred under section 8A, as it stood immediately before the commencement of the above-referred Election Laws (Amendment) Act, 1975, no such provision has been made in the case of a person disqualified by the President under Section 8A (1) after the commencement of the above-referred Amendment Act, 1975. The provisions of Section 8A (2), therefore, do not apply to a case of disqualification under section 8A (1) of the said Act.

2.2 In view of the above legal position, the Commission, in a similar petition made to the President by one Shri Balwan Singh, former member of Uttar Pradesh Legislative Assembly, had, in its opinion dated 6th April, 1981 tendered to the President, held that the petition of Shri Balwan Singh was not maintainable under any provisions of the Representation of the People Act, 1951. The President acting on the said opinion of the Commission had rejected the said petition of Shri Balwan Singh on 8th June, 1981. The law relating to the disqualification under the said section 8A (1) has not undergone any change after the said opinion was tendered by the Commission.

3. In view of the above, I am of the opinion, and accordingly hold, that the present petition of Shri Faiyazul Azam is not maintainable under any provisions of the Representation of the People Act, 1951 and is, therefore, liable to be rejected. The reference received from the President is returned to him with my opinion to the above effect.

R. V. S. PERI SASTRI,  
Chief Election Commissioner of India

New Delhi, the 28th December, 1988.

[F. No. 7 (24) [84-Leg. II]

M. K. RAMASWAMY, Jt. Secy.

